



सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 180]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 20, 2004/फाल्गुन 1, 1925

No. 180]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 20, 2004/PHALGUNA 1, 1925

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2004

का.आ. 212(अ).—यतः भवन निर्माण अनुमति की वैधता के संबंध में भवन उप-नियमों में उपयुक्त प्रावधान करने का मामला स्वीकृति की तारीख से सरकार के विचारधीन रहा है;

यतः एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया और दिनांक 10-12-2003 को समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया, जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा भवन उप-नियम, 1983 में अपेक्षित उपांतरण/परिवर्धन दिए गये थे। जनता से कोई भी आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए।

यतः केन्द्र सरकार ने भवन उप-नियम, 1983 में निम्नलिखित उपांतरण/परिवर्धन करने का निर्णय लिया है;

3. अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 11क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा इस अधिसूचना के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से भवन उप-नियम, 1983 में निम्नलिखित उपांतरण करती है।

उपांतरण :

भवन उप-नियम, 1983 के खण्ड 6.8 को निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है :—

“भवन निर्माण अनुमति के जरिए एक बार स्वीकार कर लिए जाने पर स्वीकृति रिहायशी, औद्योगिक, वाणिज्यिक भवनों तथा बड़े परिसरों और बहुमंजिला इमारतों और खंड 2.54.2, 2.54.3 और 2.54.4 के तहत वर्गीकृत भवनों के लिए स्वीकृति की तारीख से, पांच वर्षों के लिए मान्य रहेगी। इस अवधि के समाप्त होने से पूर्व भवन निर्माण अनुमति को पुनः वैध कराया जाएगा। पुनर्वैधीकरण, क्षेत्र के लिए तत्समय लागू मास्टर जोनल प्लान विनियमनों और भवन उप-नियमों के अधधीन होगा”।

[सं. के-12016/4/2003-डीडीआईबी]

जे. एस. दुआ, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND POVERTY ALLEVIATION
(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2004

S.O. 212(E).—Whereas the issue of making suitable provision in the Building Bye-laws regarding validity of building permit from the date of sanction has been under the consideration of the Government;

Whereas a public notice was issued and published in the newspapers on 10-12-2003 providing modifications/additions which the Central Government intended in the Building Bye-laws, 1983. No objection/suggestions were received from the public.

Whereas the Central Government has decided to make following modifications/additions in the Building Bye-laws, 1983;

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the Building Bye-laws, 1983 with effect from the date of this notification in the Gazette of India with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification :

Clause 6.8 of the Building Bye-laws, 1983 is revised as under :—

“The sanction once accepted through building permit shall remain valid for five years from the date of sanction for the residential, industrial, commercial buildings as well as larger complexes and multi-storeyed buildings, and such building as classified under clause 2.54.2, 2.54.3 & 2.54.4. The building permit shall be got revalidated before the expiry of this period. Revalidation shall be subject to the Master Zonal Plan regulations and Building Bye-Laws, then in force, for the area”.

[No. K-12016/4/2003-DDIB]

J. S. DUA, Under Secy.